गन्ने का समर्थन मूल्य 8.00 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1974–75 मौसम के लिए समर्थन मूल्य बढ़ा कर 8 50 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था और यह मूल्य चालू मौसम 1977–78 समेत बिना किसी परिवर्तन के बाद के मौसमो मे भी चलता रहा है। यद्यपि कृषि मूल्य आयोग ने 1975–76, 1976–77 और 1977–78 के मौसमो के लिए इसे चढा कर 9.50 रुपये प्रति क्विंटल करने की सिफारिश की थी लेकिन गन्ना (नियत्रण) आदेश, 1966 की धारा 3 के लिए जिन तथ्यो पर विचार करना अपेक्षित था, उन के समेत इस विषय से सबधित सभी सम्बद्ध तथ्यो पर गहराई से विचार करने के बाद इस मूल्य मे कोई परिवर्तन नही किया गया था।

2. वस्तुत. गन्ना उत्पादक को गन्ना (नियत्रण) आदेश, 1966 के अधीन गन्ने के निर्धारित मूल्य मे उस के गन्ने का बहुत अधिक मूल्य मिलता है। कानून के अधीन भी, गन्ना उत्पादक को गैर लेवी चीनी की बिक्री से चीनी फैक्ट्रियो को हुई अधिक प्राप्ति का 50 प्रतिशत प्राप्त करने का अधिकार है। अधिकाश राज्यो मे गन्ना उत्पादको को वह मूल्य मिलता है जिसे "राज्य द्वारा बताया गया मूल्य" कहते है। 27–10–1977 को लिए गए मत्रिमडल के निर्णय के अनुसार, राज्य सरकारो से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया जाएगा कि चीनी वर्ष 1977–78 मे गन्ने का वास्तविक मूल्य 1976–77 मे दिए गए मूल्य मे कम नही होना चाहिये। इन मूल्यो से उत्पादको को उपयुक्त रूप से पर्याप्त प्रात्साहन मिला है, जिसका गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्रफल और गन्ने के उत्पादन मे वृद्धि होने से पता चलता है। गन्ने के उत्पादन मे वृद्धि का चीनी के उत्पादन मे हुई वृद्धि से भी पता चलता है।

3. खाद्यान्नों के वसूली/साहाय्य मूल्यों में मामूली वृद्धि हुई है। क्योंकि खाद्यान्नों और गन्ने के साहाय्य मूल्यो को निर्धारित करने के लिए विभिन्न सिद्धान्त अपनाए जाते है, यह आवश्यक नही है कि खाद्यान्नों के साहाय्य मूल्य के बारे मे जिस वृद्धि की अनुमति दी गई है वैसी ही वृद्धि की अनुमति गन्ने के साहाय्य मूल्यो के बारे मे भी दी जाए।

गांधी स्मृति समिति को अनुदान

1607. श्री एम० के० शेजवलकर :
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय .

क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गाधी स्मृति समिति को अनुदान देती है ,

(ख) यदि हा, तो कितना और क्या सरकार समय-समय पर इस समिति के क्रिया-कलापों का निरीक्षण भी करती है , और

(ग) यदि हा, तो तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी हा।

(ख) और (ग) सरकार सन् 1972 से अक्तूबर, 1977 तक गाधी स्मृति समिति को 12 15 लाख रुपये अनुदान के रूप मे दे चुकी है। सरकार का स्वय समिति के साथ बहुत ही निकट का सम्बन्ध है। इस स्थान को स्मारक के रूप मे बनाए रखना इसका मुख्य कार्य है।